भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1927

दिनांक 9/8/2000 को उत्तर के लिए

हिन्दी को बढ़ावा

27. श्री जनेश्वर मिश्र:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा हिन्दी की विभिन्न सरकारी विभागों में उपेक्षा की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विभागों की संख्या कितनी है जिनमें हिन्दी में पत्राचार शतप्रतिशत नहीं किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यापक और एकीकृत कार्यक्रम शुरू करेगी ?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री (आई0 डी0 स्वामी)

(क): जी नहीं ।

(ख) और (ग): दिसंबर, 1967 में संसद के दोनों सदनों ने सरकार ~~की भांग~~ की भाषा नीति के संबंध में एक संकल्प पारित किया था जिसके पैरा-। के अनुसरण में हिंदी के प्रसार तथा विकास की गति बढ़ाने हेतु और संघ में विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके प्रयोग में तेजी लाने के लिए केंन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष एक गहन और व्यापक 'वार्षिक कार्यक्रम' तैयार कर के कार्यान्वयन हेतु सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों आदि को भेजा जाता है । केंन्द्रीय सरकार इस बारे में किए गए उपायों तथा उसमें हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक 'वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट'संसद के दोनों पटलों पर प्रस्तुत करती है और इस विषय में निरन्तर अपेक्षित और आवश्यक कदम उठाती है । तद्नुसार अन्तिम 'वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 'दिनांक 6-12-1999 और दिनांक 8-12-1999 को क्रमशः लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गई थी जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं ।

****

GOVERNMENT OF INDIA
(MINISTRY OF HOME AFFAIRS)
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.1927
TO BE ANSWERED ON 09.08.2000

PROMOTION OF HINDI

1927. SHRI JANESHWAR MISHRA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the official language Hindi is being neglected in various Government Departments ;

(b) if so, what is the number of such Departments where cent percent correspondence is not made in Hindi; and

(c) whether Government would launch any comprehensive and integrated programme to promote Hindi?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(I.D. SWAMI)

(a): No Sir.

(b)&(c): A Resolution on language policy of Government was passed by both houses of the Parliament in December, 1967. In pursuance of its para I, for accelerating the propagation and promotion of Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union, an intensive and comprehensive "Annual Programme" is prepared by the Central Government and it is send to all Ministries, Departments, Offices for implementation. An "Annual Assessment Report" giving details of the measures taken and progress achieved in this regard is laid down on the Table of both houses by the Government and takes necessary and required steps constantly in this regard. Accordingly, "Annual Assessment Report" was laid down on the tables of Lok Sabha and Rajya Sabha on 6.12.1999 and 8.12.1999 respectively. Copies of which are available in Parliament Library.

*****